लेटर्स पेटेंट अपील

एस.बी. कपूर, ए.सी.जे., और आर.एस. नरूला, न्यायमूर्ति के समक्ष

रमा वन्ति,-अपीलकर्ता

बनाम

बाल कौर, प्रतिवादी

एल.पी.ए. 1966 की संख्या 39.

1 अगस्त, 1967

लेटर्स पेटेंट - खंड 10- एकल न्यायाधीश द्वारा विवेक का प्रयोग- कब किया जा सकता है इसमें हस्तक्षेप किया गया - नागरिक प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम V) नियम 41 और आदेश 19 निवेदन आदेश 41 के नियम 1 1(2) या 17 या 18 के तहत खारिज कर दिया गया- कब अपील पुनः स्वीकार की जा सकती है उच्च न्यायालय के नियम और आदेश खंड V - अध्याय 3-ए, नियम 8 - जिन पक्षों का प्रतिनिधित्व वकील द्वारा नहीं किया गया है - अपील के ज्ञापन में दिए गए पते से भिन्न पते पर अपीलकर्ता को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा गया है। क्या नोटिस भेजा गया है

माना गया कि लेटर्स पेटेंट अपील में एकल न्यायाधीश द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप का सहारा तब तक नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि विवेक का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया गया हो।

माना गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 19 के तहत, जैसे ही अदालत संतुष्ट हो जाती है कि किसी अपीलकर्ता को किसी पर्याप्त कारण से अदालत में उपस्थित होने से रोका गया था जब उसकी अपील सुनवाई के लिए बुलाई गई थी, अदालत लागत या अन्य शर्तों जैसे वह उचित समझे जाने पर अपील को दोबारा स्वीकार करने के लिए बाध्य है।

माना गया कि उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के खंड V के अध्याय 3-ए के नियम 8 के तहत यह उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री का कर्तव्य है कि वह उन पक्षों को नोटिस जारी करे जो; पंजीकृत एडी डाक द्वारा वकील द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है और इसे "अपील के ज्ञापन में अपीलकर्ता द्वारा दिए गए पते पर" भेजने के लिए कहा जाता है। मैं, केवल एक पोस्टकार्ड की पोस्टिंग है जिसे मामले में तय तारीख की पार्टी के लिए पर्याप्त सूचना माना जाता है। यदि न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि अपील की सुनवाई की वास्तविक

तारीख का नोटिस अपीलकर्ता को दिया जाए, तो अपील को तब तक खारिज नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे ऐसा नोटिस नहीं दिया जाता। अपीलकर्ता को ज्ञापन में दिए गए पते से भिन्न पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया नोटिस पर्याप्त सेवा नहीं माना जा सकता है यदि नोटिस उस तक नहीं पहुंचा है।

लेटर्स पेटेंट अपील, लेटर्स पेटेंट के क्लॉज 1963 की संख्या 358. माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.के. महाजन के दिनांक 14///जनवरी, 1966 के आदेश के विरुद्ध, ई.एफ.ए. 1963 की संख्या 358 की बहाली के लिए याचिका को खारिज कर दिया गया।

अपीलकर्ता की ओर से वकील एल.एम. सूरी।

प्रतिवादी की ओर से राम रंग, अधिवक्ता।

निर्णय

नरूला, जे- लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश के 14 जनवरी 1966 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें बहाली के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 19 के तहत अपीलकर्ता के एक आवेदन को खारिज कर दिया गया था। 1963 की उनकी निष्पादन प्रथम अपील संख्या 358, जो उन्होंने श्री दुर्गा दास खन्ना के माध्यम से दायर की थी, जो उस समय इस न्यायालय में वकालत कर रहे थे। अपील 21 अक्टूबर, 1963 को स्वीकार की गई। जब यह 5 अगस्त, 1965 को अंतिम सुनवाई के लिए पहुंची, तो यह पाया गया कि अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था, क्योंकि उसके वकील को इस बीच पंजाब विधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इसलिए, गुरदेव सिंह, जे., जिनके समक्ष अपील सूचीबद्ध की गई थी, ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को उपस्थित होने और अपील पर मुकदमा चलाने के लिए एक वास्तविक तारीख का नोटिस जारी किया जाए। यद्यपि अपीलकर्ता ने न केवल निष्पादन प्रथम अपील के साथ दायर पार्टियों के ज्ञापन में अपना पता दिया था, बल्कि पूरे मुकदमे में 2/7 वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली का पता दिया था, ए. डी. नोटिस पोस्टकार्ड में उसे आर-102 वेस्ट पटेल नगर^ नई दिल्ली पर संबोधित किया गया था। 12 अगस्त, 1965 का पोस्टकार्ड, जो 17 सितंबर, 1965 के लिए निर्धारित वास्तविक तारीख की सुनवाई

के लिए जारी किया गया था, प्राप्तकर्ता को बिना डिलीवर किए वापस प्राप्त हो गया। 30 सितंबर, 1965 को जब मामला फिर से गुरदेव सिंह, जे. के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो उपरोक्त स्थिति में, उपरोक्त नोटिस अभी तक वापस नहीं आया था। और इसलिए, डाक विभाग से पूछताछ के लिए मामला 11 अक्टूबर, 1965 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विद्वान न्यायाधीश द्वारा आगे यह निर्देश दिया गया कि इस बीच अपीलकर्ता को पंजीकृत डाक द्वारा उस तारीख के लिए एक नया नोटिस जारी किया जा सकता है। हालाँकि, दुर्भाग्य से, ताजा नोटिस फिर से एक पते पर जारी किया गया था, जिसमें लिखा है आर-102, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली, जो कि अपीलकर्ता का पता कभी नहीं था। मामला 11 अक्टूबर 1965 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, वास्तव में 15 अक्टूबर 1965 को महाजन, जे. के समक्ष सुनवाई हुई। चूँकि अपीलकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, अपील को बिना उपस्थिति के डिफ़ॉल्ट के कारण विद्वान न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया। प्रतिवादी के वकील की उपस्थिति में लागत के संबंध में कोई भी आदेश पास नहीं किया गया।

अपीलकर्ता के अनुसार, वह 12 नवंबर, 1965 को चंडीगढ़ आईं और पूछताछ करने पर पता चला कि उनकी अपील डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने अपील को दोबारा स्वीकार करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 19 के तहत 15 नवंबर, 1965 को सिविल विविध 2295-सी, 1965 दायर किया। आवेदन में, जिसे अपीलकर्ता के हलफनामे द्वारा विधिवत समर्थित किया गया था, उसने कहा था कि गुरदेव सिंह, जे. द्वारा आदेशित किसी भी नोटिस के बिना अपील को सुनवाई के लिए रखा गया था, और नोटिस जारी किए गए थे इस न्यायालय के कार्यालय को गलत पते पर भेजा गया था, जैसा कि निष्पादन प्रथम अपील में पार्टियों के ज्ञापन पर दिए गए अपीलकर्ता के पते की तुलना में नोटिस पर दिए गए पते से स्पष्ट होगा। इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश, जिनके समक्ष यह आवेदन सुनवाई के लिए आया था, ने 14 जनवरी, 1966 के आदेश द्वारा इसे तुरंत खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने यह अपील दायर की है।

अपील को पुनः स्वीकार करने के आवेदन में अपीलकर्ता का सही पता उद्धृत नहीं किया गया था। न ही उस पते का उल्लेख किया गया था जिस पर अपीलकर्ता को दो नोटिस जारी किए गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पतों के बीच का अंतर विद्वान न्यायाधीश के ध्यान में नहीं लाया गया है।

इस अपील का प्रतिवादी द्वारा विरोध किया गया है। उनके विद्वान वकील श्री राम रंग ऊपर बताए गए किसी भी तथ्य पर सवाल उठाने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हनुमान चैंबर ऑफ कॉमर्स लिमिटेड, दिल्ली बनाम मेसर्स आर.बी. सेठ जस्सा राम-हीरा नंद(1), मामले में लाहौर उच्च न्यायालय के अधिकार पर केवल बहस की है। कि एक लेटर्स पेटेंट में विवेक के प्रयोग में हस्तक्षेप की अपील की गई है किसी विद्वान एकल न्यायाधीश का सहारा तब तक नहीं लिया जाना चाहिए जब तक यह न पाया जाए कि विवेक का प्रयोग मनमाने ढंग से किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वकील अपनी दलील में सही है, लेकिन यह तर्क वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है क्योंकि संहिता के आदेश 41 के नियम 19, जो नीचे उद्धृत किया गया है, किसी न्यायालय को कोई विवेकाधिकार प्रदान नहीं करता है: -

> "जहां नियम 11, उप-नियम (2) या नियम 17 या नियम 18 के तहत अपील खारिज कर दी जाती है, अपीलकर्ता अपील को पुनः स्वीकार करने के लिए अपीलीय न्यायालय में आवेदन कर सकता है; और, जहां यह साबित हो जाता है कि जब अपील सुनवाई के लिए बुलाई गई थी तो उसे उपस्थित होने से या आवश्यक राशि जमा करने से किसी पर्याप्त कारण से रोका गया था, अदालत लागत या अन्यथा जैसी शर्तों पर अपील को दोबारा स्वीकार करेगी। उचित समझता है।"

जैसे ही न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि किसी अपीलकर्ता को किसी पर्याप्त कारण से अदालत में उपस्थित होने से रोका गया था जब उसकी अपील सुनवाई के लिए बुलाई गई थी, तो न्यायालय लागत या अन्य शर्तों पर अपील को दोबारा स्वीकार करने के लिए बाध्य है। जैसा वह उचित समझे। इसलिए, इस मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किसी भी विवेक का प्रयोग करने का कोई सवाल ही नहीं है। उपर्युक्त रिकॉर्ड के अवलोकन से, जो विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया प्रतीत होता है, हम संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ता को पर्याप्त कारणों से उपस्थित होने से रोका गया था जब उसकी निष्पादन पहली अपील 15 अक्टूबर 1965 को सुनवाई के लिए बुलाई गई थी। यह न्यायालय की रजिस्ट्री का कर्तव्य है (इस न्यायालय के नियमों और आदेशों के खंड V के अध्याय 3-ए के नियम 8 के तहत) उन पक्षों को नोटिस जारी करें जिनका प्रतिनिधित्व पंजीकृत ए.डी. पोस्ट द्वारा वकील द्वारा नहीं किया गया है और इसे "अपीलकर्ता द्वारा

(1) 1947 पी.एल.आर. 230.

अपील के ज्ञापन में दिए गए पते पर" भेजने के लिए। यह केवल ऐसे पोस्टकार्ड की पोस्टिंग है जिसे मामले में तय तारीख की पार्टी के लिए पर्याप्त सूचना माना जाता है। ऊपर उल्लिखित नियम 8 का पहला परंतुक निम्नलिखित शर्तों में है: -

> “बशर्ते किसी मामले में तय की गई पक्की तारीख की सूचना पंजीकृत पोस्टकार्ड (ए.डी.) द्वारा ऐसे पक्षों को भेजी जाएगी जिनका प्रतिनिधित्व वकील द्वारा नहीं किया गया है। ऐसा पोस्टकार्ड अपील के मूल नोटिस के जवाब में पार्टी द्वारा दिए जाने वाले पते पर भेजा जाएगा, जिसमें अपील के प्रयोजनों के लिए सेवा के लिए एक पता प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा, या यदि वह एक माह के भीतर अपील की ऐसी सूचना की सेवा, अपीलकर्ता द्वारा अपील के ज्ञापन में दिए गए पते पर देने में विफल रहता है अपील की ऐसी सूचना की तामील अपीलकर्ता द्वारा अपील के ज्ञापन में दिए गए पते पर की जाएगी। ऐसे पोस्टकार्ड की पोस्टिंग को मामले में तय तारीख की पार्टी को पर्याप्त सूचना माना जाएगा।

चूँकि यह पार्टियों का सामान्य मामला है कि अपीलकर्ता के वकील श्री डी. डी. खन्ना ने निष्पादन की पहली अपील सुनवाई के लिए आने के समय तक पेशा छोड़ दिया था और चूंकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश दिया था कि सुनवाई की वास्तविक तारीख की सूचना दी जाए। उसकी अपील अपीलकर्ता को दी जा सकती है, जब तक उसे ऐसा नोटिस नहीं दिया जाता तब तक अपील को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में, हम इस अपील की अनुमति देते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 19 के तहत अपीलकर्ता के आवेदन को खारिज करने के आदेश को रद्द करते हैं और 1963 की निष्पादन प्रथम-अपील संख्या 358 को फिर से स्वीकार करते हैं, और आगे निर्देश देते हैं उसी तरह 21 अगस्त 1967 को किसी एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। मामले की परिस्थितियों में, इस अपील की लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

एस.बी. कपूर, ए.सी.जे.- मैं सहमत हूं।

आर.एन.एम.

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया

जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रिंस कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी